

भारत सरकार  
खान मंत्रालय  
लोक सभा  
अतारांकित प्रश्न सं. †3142  
दिनांक 11.03.2026 को उत्तर देने के लिए  
आयातित दुर्लभ मृदा तत्वों पर निर्भरता

†3142. सुश्री सयानी घोष:

क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने ऑटोमोबाइल, रक्षा उत्पादन, इलेक्ट्रॉनिक्स, नवीकरणीय ऊर्जा और इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए महत्वपूर्ण दुर्लभ मृदा तत्वों के आयात पर भारत की निर्भरता का आकलन किया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) वर्ष 2014 से भारत के दुर्लभ मृदा आयात में मात्रा/मूल्य और चीन की हिस्सेदारी का वर्ष और तत्व-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि यद्यपि भारत के पास वैश्विक दुर्लभ मृदा भंडार का अनुमानित 6 से 8 प्रतिशत हिस्सा है, लेकिन वैश्विक उत्पादन में इसकी हिस्सेदारी एक प्रतिशत से भी कम है और इस अल्प-उपयोग के क्या कारण हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने दुर्लभ मृदा सामग्रियों पर चीन के हालिया निर्यात प्रतिबंधों, विशेष रूप से वर्ष 2025 में, से उत्पन्न रणनीतिक जोखिमों का मूल्यांकन किया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या ऑटोमोबाइल, रक्षा, ईवी, अर्धचालक और इलेक्ट्रॉनिक्स को प्रभावित करने वाले संभावित आपूर्ति व्यवधानों की जांच के लिए कोई प्रभाव आकलन किया गया है और यदि हाँ, तो क्षेत्र-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) 'इंडियन रेयर अर्थ्स लिमिटेड' द्वारा की गई पहलों सहित दुर्लभ मृदा के घरेलू अन्वेषण, खनन, पृथक्करण और प्रसंस्करण की वर्तमान स्थिति क्या है?

उत्तर

कोयला और खान राज्य मंत्री  
(श्री सतीश चंद्र दूबे)

(क) से (च): परमाणु ऊर्जा विभाग (डीएई) की एक घटक इकाई परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय (एएमडी) देश के तटीय/अंतर्देशीय/तटवर्ती प्लेसर रेत में दुर्लभ मृदा तत्वों (आरईई) का गवेषण करता है, जिनमें मोनाज़ाइट सहित दुर्लभ मृदा खनिज शामिल हैं। आज तक, एएमडी ने आरईई के अनुमानित संसाधन को निम्नानुसार सिद्ध किया है:

- लगभग 7.23 मिलियन टन दुर्लभ मृदा ऑक्साइड (आरईओ) 13.15 मिलियन टन मोनाज़ाइट संसाधन में निहित के बराबर है, जो केरल, तमिलनाडु, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात के कुछ हिस्सों में तटीय समुद्र तट तथा टेरी/लाल रेत में और झारखंड, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में अंतर्देशीय जलोढ़ में पाया जाता है।
- गुजरात के छोटा उदेपुर जिले के अम्बाडुंगर क्षेत्र और राजस्थान के बालोतरा जिले के भाटीखेडा और दंतला क्षेत्र में कठोर चट्टान क्षेत्रों में 1.29 मिलियन टन स्वस्थाने आरईओ।
- छत्तीसगढ़ और झारखंड के तटवर्ती प्लेसर निक्षेपों में ~2% ज़ेनोटाइम (इट्रियम और भारी दुर्लभ मृदा तत्वों का एक फॉस्फेट खनिज) युक्त 2,000 टन भारी खनिज सांद्रता।

डीई के अधीन एक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम आईआरईएल (इंडिया) लिमिटेड को भारत में मोनाज़ाइट खनिज युक्त दुर्लभ मृदा से उच्च शुद्धता वाले दुर्लभ मृदा ऑक्साइड के रूप में दुर्लभ मृदा तत्वों का उत्पादन करना अनिवार्य है। आईआरईएल में खनिज रेत के एकीकृत खनन और प्रसंस्करण तथा दुर्लभ मृदा के निष्कर्षण एवं शोधन की सुविधाएं मौजूद हैं।

भारत के पास दुर्लभ मृदा संसाधनों की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता और उनके निष्कर्षण एवं शोधन के लिए पर्याप्त क्षमता होने के बावजूद पर्याप्त प्रौद्योगिकी की कमी और आरईई मूल्य श्रृंखला में मध्य-स्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम उद्योगों की अनुपस्थिति के कारण इन खनिजों का वाणिज्यिक खनन और प्रसंस्करण सीमित रहा है। वर्तमान में, आरईई प्रसंस्करण पर एक देश का प्रभुत्व है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने आरईई सहित महत्वपूर्ण खनिजों के लिए घरेलू उत्पादन बढ़ाने और आपूर्ति के स्रोतों में विविधता लाने के लिए कई कदम उठाए हैं।

सरकार ने महत्वपूर्ण खनिजों (आरईई सहित) की दीर्घकालिक सतत आपूर्ति सुनिश्चित करने और खनिज गवेषण एवं खनन से लेकर सज्जीकरण, प्रसंस्करण तथा एंड-ऑफ- लाइफ उत्पादों से पुनः प्राप्ति तक सभी चरणों को शामिल करते हुए भारत की महत्वपूर्ण खनिज मूल्य श्रृंखला को सुदृढ़ करने के लिए 29 जनवरी, 2025 को राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन (एनसीएमएम) को अनुमोदित किया है। वित्त वर्ष 2026-27 के लिए केंद्रीय बजट में खनन, प्रसंस्करण, अनुसंधान और विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए समर्पित दुर्लभ मृदा कॉरीडोर स्थापित करने के लिए ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु जैसे खनिज सम्पन्न राज्यों को सहायता प्रदान करने की घोषणा की गई है।

आयात डेटा का देश-वार और मद-वार ब्यौरा, वाणिज्य विभाग की वेबसाइट (<https://tradestat.commerce.gov.in>) पर उपलब्ध है।

\*\*\*\*\*